IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved Journal UGC CARE Listed (Group-I) Volume 07, Issue 01, 2018

कृषि व्यवसायीकरण और कृषि औद्योगिकरण

(जनपद देवरिया के संदर्भ में।)

डॉ० सत्यकीर्ति सिंह

प्रवक्ता भूगोल विभाग, आदर्श सतेन्द्र महाविद्यालय माल लखनऊ उत्तर प्रदेश

शोध सारांश

राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृरि के बावजूद गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के विभिन्न प्रखंडों में विकास हुआ है परंतु क्षेत्रीय स्तर पर विकास का स्तर की प्रवृत्ति में व्यवधान उत्पन्न कर दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हास हुआ। 18 वीं शताब्दी में यूरोप की औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे विश्व में परिवर्तन का एक दौर प्रारंभ हुआ। तीव्र विकास के कारण उपनिवेश का दौर प्रारंभ बहुत ही मंद है अस्तु विकास प्रक्रिया के क्षेत्रीय प्रतिरूप को हुआ। इसी समय भारत में अंगजी शिक्षा की स्थापना एवं उसकी उभारने के लिए स्थानीय संसाधनों के विकास के साथ ही जनता की सहभागिता भी आवश्यक है। कृषि अर्थ तंत्र व्यवस्था वाले क्षेत्रों में जहां खनिज संसाधनों का प्रायः अभाव है तथा जनसंख्या संसाधन की प्रचुरता है। वहां सामाजिक, आर्थिक, अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास के द्वारा समुचित विकास प्रतिरूप को प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि का प्रारंभ मानवीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पूर्व मानव की जीविकोपार्जन का मूल स्रोत मांस एवं कंदमूल ही थे, जो इनको स्थानांतरणशील बनाए रखा, परंतु सभ्यता के इस विकास से इनमें एक नई चेतना का विकास हुआ। प्रारंभिक चरण में पौधों का घरेलूकरण तथा उनको भूमि में दबाकर उगाने की प्रक्रिया के द्वारा कृषि तकनीक का सूत्रपात हुआ और यहीं से कृषि किसी का क्रमिक विकास भी प्रारंभ हुआ। नदी घाटियों की उर्वर भूमि में अन्न के दाने बिखेरकर दबा दिए जाते थे और कृषि उत्पाद प्राप्त किए जाते थे। एक स्थान की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर पुनः दूसरी उर्वरा भूमि पर कृषि का उत्पादन शुरू हो जाता था जिससे स्थानांतरण कृषि का विकास हुआ। कालांतर में मानव सभ्यता का विकास एवं कृषि तकनीक में विकास केफलस्वरूप कृषि में स्थायित्व तथा तकनीक में विकास हुआ। इस प्रकार कृषि स्थायीकरण और प्राविधिक विकास के द्वारा विकसित कृषि एवं व्यवसायिक कृषि का सूत्रपात हुआ।

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

प्राचीन भारत जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। प्राचीन काल में भारतीय समाज के अन्य वर्ग के लिए एवं कुछ हिस्सा पुनः कृषि बीज के रूप में सुरक्षित रखा जाता था । ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संचालन में श्रम का स्पस्ट वर्गीकरण था, जिसमें समाज का एक वर्ग कृषि कार्यों में ही संलग्न रहता था और इनमें इनमें विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय था क्योंकि कृषि उत्पाद के बदले यह अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करते थे, परंतु नगरीय प्रवृत्ति ने श्रम विभाजन शोषण की नीति के फलस्वरूप कृषि में नगदी फसल पर विशेष जोर दिया गया, परंतु कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति एवं कृषको के विकास पर कोई ध्यान हीं दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में ह्रास हुआ। साथ ही नगदी फसल पर अधिक ध्यान देने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, जिससे किसानों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया गया, जिसमें कृषि के विकास को प्रमुखता से लिया गया । कृषि के विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मसाले, जड़ी बूटियां तथा कपास और इसके रेशे से बनी सूती वस्त्रों के अतिरिक्त गन्ने से बनी सफेद शक्कर के निर्यात का सिलसिला बहुत पुराना है । भरण-पोषण के उपयोग के बाद बचे कृषि उत्पादों का व्यापार प्राचीन भारत में भी किया जाता था। पतंजलि के महाभाष्य जातक के अतिरिक्त अनेक प्राचीन ग्रंथों में कृषि वाणिज्य का उल्लेख मिलता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरुप कृषि में उत्पादन बढ़ने से उसके निर्यात एवं आधारित उद्योगों का विकास हुआ है।

इस प्रकार भौगोलिक रूप में कहा जा सकता है कि कृषिगत अर्थ तंत्र का ही एक प्रगतिशील रूप कृषि का व्यावसायीकरण है। जिससे कृषि में पूँजी निवेश और लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया में अर्थ तंत्र में परिवर्तन होता रहता है। भारत जैसे देश में यहां की लगभग 80 की जनसंख्या से अधिक कृषि पर ही आश्रित हैं। यही नहीं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कृषि ही है। जिससे अर्थतन्त्र प्रभावित होता है। इसीलिए कृषि का व्यावसायीकरण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में एक सकारात्मक कदम है। कृषि के व्यावसायीकरण के परिणाम स्वरूप क्षेत्र विशेष में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं अनेक उद्योग विकसित होते हैं जबकि कुछ विशेष उद्योग की स्थापना से शस्यक्रम में परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया, यातायात एवं परिवहन के विकास, बदलती सभ्यताएं, नवाचारों का प्रसार आदि कारणों से आई हैं। इस प्रकार स्पष्ट है किसी क्षेत्र विशेष में कृषि अर्थतंत्र में यदि ऐसे तत्वों

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

का प्रसार-प्रचार किया जाए तो स्वभावतः कृषि का व्यावसायीकरण होता रहेगा और यह व्यावसायीकरण क्षेत्र विशेष के पारिस्थितिकीया संस्लिस्ट अनुकूल रहने पर और अधिक उपयोगी सि (हो सकता है।

कृषि का व्यावसायीकरण और कृषि औद्योगिकरण

यद्यपि संकलनात्मक रूप में किसी भी क्षेत्र के उद्योगों के विकास की प्रक्रिया का सूत्रपात, वहां उपलब्ध संसाधनों, शक्ति संसाधनों, परिवहन, विपणन, विविध तकनीकों का ज्ञान, अन्य अवस्थापना तत्वों के विकास तथा सरकारी नीतिगत निर्णयों द्वारा होता है। तथापि यह भी सत्य है कि विभिन्न उद्योगों में प्राथमिक उत्पादों का द्वितीयक एवं तृतीयक स्वरुप निर्मित होता है। इसीलिये परिवहन श्रम, पूँजी एवं संबंधी एवं अन्य अवस्थापनात्मक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर किसी भी क्षेत्र विशेष में कृषि आधारित उद्योगों का विकास संभव होता है। साथ ही साथ तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या से कृषि क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को कम करने, बेरोजगारी से छुटकारा पाने, निघ् निता एवं आर्थिक विषमता को कम करने तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु कृषि पैर आधारित कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जा सकता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृषि का व्यवसायीकरण और कृषि औद्योगीकरण एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य व्यावसायिक कृषि अथवा कृषि में बदलाव से है, जिसमें नगदी फसलों की प्रधानता होती है और अन्य फसल गौण हो जाती है। कृषि औद्योगिकीकरण से तात्पर्य कृषि क्षेत्रों में कृषि पर आधारित अनेक प्रकार उद्योग धंधों की स्थापना से है। दूसरे शब्दों में कहा जा

सकता है कृषि व्यवसायीकरण का अगला विकसित रूप कृषि औद्योगिकरण है। इस प्रकार क्षेत्र विशेष में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति होने पर रोजगार सृजन, पूँजी निर्माण, कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार, क्षेत्रीय विकास परिवहन विकास आदि प्रक्रिया स्वतः विकसित हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि औद्योगिकरण को ग्रामीण विकास का एक निर्धारक माना जा सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थतंत्र में औद्योगिकरण एक आसान प्रक्रिया है जो आधुनिक उदारवादी अर्थ तंत्र में विकासात्मक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण का पर्याय मानी जा सकती हैं। संभवतः गांधी जी ने अपने आर्थिक दर्शन में ग्राम स्वराज सर्वोदय आदि संकल्पनाओं को इसलिए विकसित किया था ताकि देश के अर्थ तंत्र में आर्थिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया विकसित न होकर संतुलित आर्थिक विकास हो सके।

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

जिससे ग्रामीण जनसंख्या का पलायन नगरों की ओर ना हो। इसलिए कृषि औद्योगीकरण का विकसित होना क्षेत्रीय अर्थतंत्र की विकासात्मक सभ्यताओं को स्पष्ट करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों में तीव्र गति से विकास हुआ, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर विकास की लहर बहुत ही धीमी रही। अस्तु विकास की प्रक्रिया के क्षेत्रीय प्रतिरूप को उभारने के लिए स्थानीय संसाधनों के विकास के साथ ही साथ जनता की सहभागिता की आवश्यकता महसूस की गई। अविकसित तथा अल्पविकसित कृषि अर्थ तंत्र वाले क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया के समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर संसाधनों के विकास द्वारा ही समुचित ग्रामीण विकास प्रतिरूप को प्राप्त किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र जनपद देवरिया के संदर्भमें ऐतिहासिक तथ्य यह स्पष्ट करता है कि यहां जनसंख्या का आकर्षण हमेशा रहा है। यह प्राचीन काल से ही सुगम्य क्षेत्र, उर्वर मिटटी, जल की समुचित उपलब्धता एवं उपयुक्त मानसूनी वर्सा से युक्त रहा है। इसीलिए विभिन्न राजाओं ने अपने किलों का निर्माण कराया और कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की।

यहां पर विभिन्न समयों में कृषि में परिवर्तन एवं विकास हुआ, प्राचीन काल में जीविकोपार्जन के रूप में कृषि की जाती थी । जिसमें खाद्यान्नों की प्राथमिकता रहती थी । ब्रिटिश काल में नगदी फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। जिससे खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट आई। जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होती गई, परिणाम स्वरूप कृषि पर बुरा असर पड़ा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि के विकास में प्रगति हुई। देश की पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ क्षेत्र को भी मिला और कृषि के विकास के परिणामस्वरूप अध्ययन क्षेत्र खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। यहां नगदी फसलों का विकास हुआ है। नगदी फसलों से तात्पर्य खाद्यान्न फसलों के अलावा उगाई जाने वाली उन फसलों से है, जिनका किसानों को तत्काल मूल्य प्राप्त होता है। चूँकि इन फसलों का विभिन्न प्रकार के व्यापारिन जात अतः इन्हें व्यापारिक फसल की 3/6 तथा इनके कृषि को व्यापारिक है। यही कृषि उत्पाद विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते। इस प्रकार इस प्रसंग में इन फसलों को फसलों विभिन्नता मिलती है। तालिका संख्या 3.1 के अवलोकन से स्पस्ट है कि जनपद देवरिया कि संपूर्ण सस्यगत भूमि के मात्र 7.78 [भू-भाग पर ही व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न फसलों के अंतर्गत सम्मिलित भू-भाग में और भी भिन्नता मिलती है जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। तालिका

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

संख्या 3.1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की व्यापारिक फसलों के अंतर्गत भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल गन्ना के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जबकि सबसे कम सोयाबीन के अंतर्गत है। जो कुल सस्यगत भूमि का मात्र 0.004 है। अध्ययन क्षेत्र में गन्ना का सर्वाधिक क्षेत्र है जो कुल शस्य भूमि का 5.72 चूंकि यहाँ गन्ना बड़े पैमाने पर उगाया जाता है।

व्यापारिक फसलों के अंतर्गत लगी भूमि का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया जाए तो तालिका संख्या 3.2 से स्पस्ट होता है कि जनपद देवरिया के चार विकास खंडों में बैतालपुर, देसाई देवरिया, पथरदेवा और बनकटा में 10 से भी अधिक भूमि पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं।

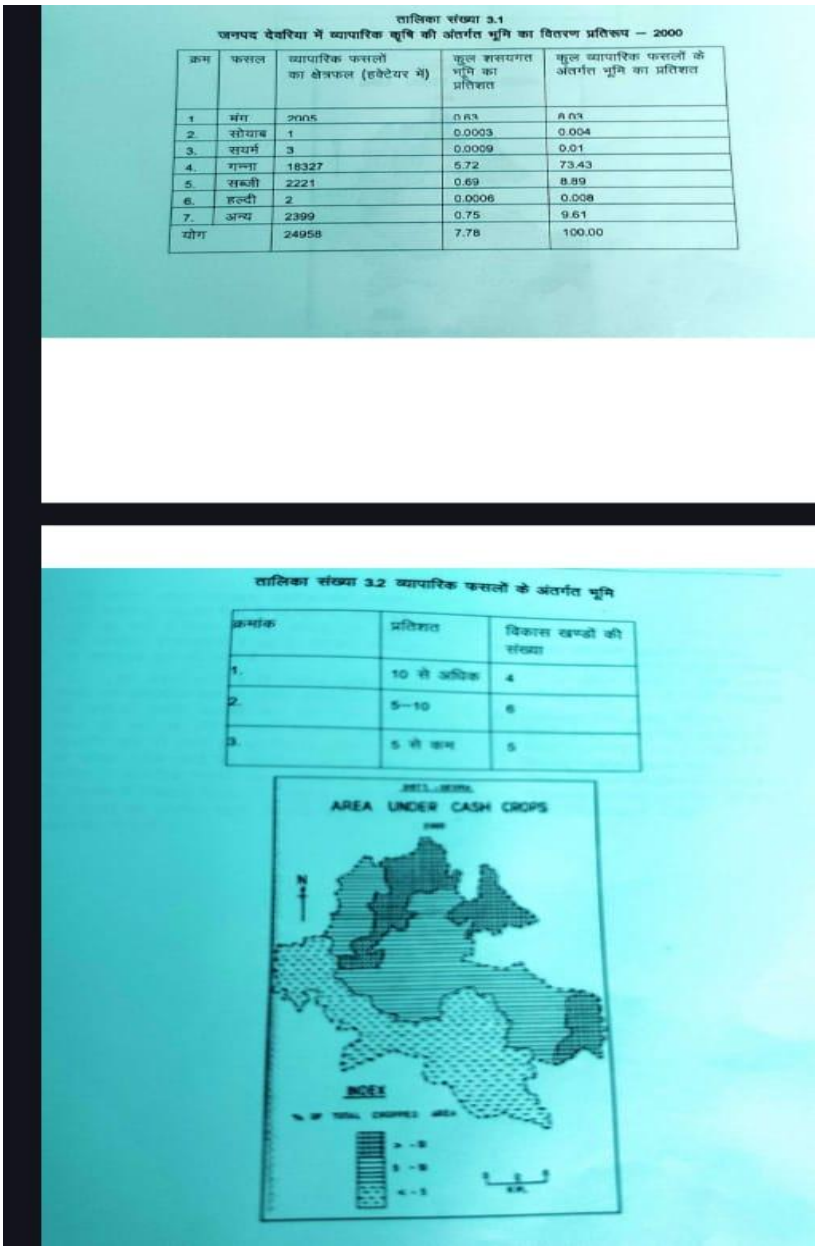

तालिका संख्या 3.1
जनपद देवरिया में व्यापारिक कृषि की अंतर्गत भूमि का वितरण प्रतिरूप – 2000

क्रम	फसल	व्यापारिक फसलों का क्षेत्रफल (हजेटेयर में)	कुल शस्यगत भूमि का प्रतिशत	कुल व्यापारिक फसलों के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत
1.	मंग	2005	0.63	8.03
2.	सोयाब	1	0.0003	0.004
3.	सयर्म	3	0.0009	0.01
4.	गन्ना	18327	5.72	73.43
5.	सब्जी	2221	0.69	8.89
6.	हल्दी	2	0.0006	0.008
7.	अन्य	2399	0.75	9.61
योग		24958	7.78	100.00

तालिका संख्या 3.2 व्यापारिक फसलों के अंतर्गत भूमि

क्रमांक	प्रतिशत	विकास खण्डों की संख्या
1.	10 से अधिक	4
2.	5–10	6
3.	5 से कम	5

AREA UNDER CASH CROPS

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, देवरिया सदर, भाटपार रानी, भटनी एवं भलुअनी में 5 से 10 भूमि पर व्यावसाइक कृषि की जाती है, जबकि सलेमपुर, बरहज, लार, रूद्रपुर एवं भागलपुर विकासखंडों में 5 से भी कम क्षेत्रफल पर व्यवसाइक कृषि की जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जनपद देवरिया का उत्तरी एवं पश्चिमोत्तर भाग पर अधिक व्यावसायिक कृषि की जाती है, जबकि मध्यवर्ती भाग तथा कुछ हिस्सा उत्तर पूर्व का एवं पश्चिमी भाग में मध्यम स्तर की व्यापारिक कृषि की जाती है। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व में यह क्रमशः घटती जाती है। भौगोलिक रूप में जनपद देवरिया में व्यापारिक फसलों और पारिस्थितिकीय तत्वों के वितरण में समानता मिलती है। उपजाऊ दोमट मिट्टी और सिंचाई की समुचित साधन ने गन्ना की कृषि को प्रोत्साहित किया है।

REFERENCES

1- तिवारी अखिलेश; 2000 द्ध- सामाजिक वानिकी ग्रामीण विकास नियोजन पुरूलिया जनपद पश्चिम वंगाल का प्रतीक अध्ययन अप्रकाशित दी द उ गो वि वि गोरखपुरद्ध

2- Chauhan P R (1998), Politics Environment and Development in Madhya Pradesh in D K Singh, R S Dubey, V K Srivastava (eds.) Geography development and change NP Ayyar Commemorative volume A

MGI Gorakhpur, 2000.